शिव शंकर दाल मिल्स इत्यादि

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

9 नवंबर, 1979

[वी.आर. कृष्णा अय्यर, आर.एस. पाठक और ए.डी. कौशल, जे.जे.]

भारत का संविधान 1950, अनुच्छेद 226-उच्च न्यायालय ने वसूली को अवैध ठहराया - धनवापसी के लिए विशिष्ट दायित्व - वैकल्पिक उपाय 'उपलब्ध'- क्षेत्राधिकार के तहत - क्या वर्जित है।

केवल कृष्ण पुरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य [1979] 3 एस.सी.आर. पृष्ठ 1217, इस न्यायालय ने 1977 के हरियाणा अधिनियम संख्या 22 के तहत 3 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर (मूल 2 प्रतिशत से बढ़ाकर) पर बाजार शुल्क का भुगतान रद्द कर दिया। इसलिए बाजार समितियों पर एकत्र की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का परिणामी दायित्व डाला गया था।

अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने गलती से अतिरिक्त रकम का भुगतान कर दिया था, ने इस आशय का निर्देश देने की मांग की कि ये रकम वापस कर दी जाए।

बाजार समितियों द्वारा एकत्र की गई अतिरिक्त राशि की वापसी के सवाल पर।

अभिनिर्धारित किया: 1. जहां सार्वजनिक निकाय सार्वजनिक कानूनों के तहत लोगों का पैसा वसूलते हैं, बाद में गलत वसूली होने का पता चला, स्थिति का धर्म

किसी भी प्रकार की बातचीत न करना स्वीकार करता है। विशेष रूप से सार्वजनिक निकायों के लिए गलत तरीके से बरामद की गई चीज़ को वापस करने की सीमा का कोई कानून नहीं है। हमारे न्यायशास्त्र में वैकल्पिक उपचार की नकारात्मक दलील पर उच्च विशेषाधिकार रिट के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि न्याय से जुड़े कानून का मूल सिद्धांत जहाँ अधिकार है, वहां उपाय है। [1172 जी-एच]

2. हमारे अधिकार क्षेत्र में, सामाजिक न्याय एक व्यापक उपस्थिति है; और इसलिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, न्यायिक प्रक्रिया की सेवा का दावा करने वालों से वितरणात्मक न्याय के बुनियादी नियम को अपनाने के लिए कहकर राहत की रूपरेखा तैयार करते समय, छोटे व्यक्तियों से, जिनसे वे संबंधित हैं, छोटे-छोटे लेन-देन में ली गई थोड़ी-थोड़ी रकम वापस करने की सहमति देकर समानता की रणनीति द्वारा निर्देशित होना उचित है [1173 ई]

3. अनुच्छेद 226 एक असाधारण उपाय प्रदान करता है जो अनिवार्य रूप से विवेकाधीन है, हालांकि कानूनी चोट पर आधारित है। यह न्यायालय के लिए पूरी तरह से खुला है कि इस लचीली शक्ति का उपयोग सार्वजनिक हित के आदेशों और इक्विटी परियोजनाओं जैसे आदेश पारित करने के लिए किया जा सके। [1174 डी]

मौजूदा मामले में हालांकि अतिरिक्त संग्रह की वापसी कानूनी रूप से व्यापारियों के कारण हो सकती है, कई व्यापारियों ने स्वयं अगले खरीदारों से अतिरिक्त प्रतिशत की वसूली की थी। जिस हद तक व्यापारियों ने अपना खुद का भुगतान किया था, वे उन्हें रखने के हकदार थे, लेकिन वहां नहीं जहाँ उन्होंने बदले में कहीं और से पैसा इकठ्ठा किया था। प्रत्येक कृषक के लिए यह मुश्किल होगा कि वह न के बराबर राशि की वसूली के लिए मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही दायर करे जो संचयी रूप से भारी राशि है। [1173 एफ-एच]

4. नवाबगंज शुगर मिल्स बनाम भारत संघ और अन्य [1976] 1 एस.सी.आर. 803 में इसी तरह की स्थिति में इस न्यायालय ने एक नई स्थिति से निपटने के लिए एक नई प्रक्रिया तैयार की जहां इक्विटी ने पुनर्वितरण की मांग की लेकिन प्रक्रियात्मक महँगाई और बोझिलता ने कानूनी कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। [1173 एच-1174 ए]

5. पूर्ववर्ती के बिना स्थितियाँ पूर्ववर्ती के बिना उपचार की मांग करती हैं। [1174 बी]

[न्यायालय ने बाजार समितियों द्वारा धन वापसी और उन लोगों को छोटी रकम के पुनर्वितरण की एक योजना तैयार की, जिनसे अनुचित संग्रह किया गया था।] [1174 सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3220-3234/1979

सिविल रिट याचिका संख्या 2306, 2966, 2737, 3617, 2588, 3277, 3749, 3697, 3820, 3625, 3624 और 315-317/79 क्रमशः में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11-7-79, 23-8-79, 8-8-79, 15-10-79, 30-7-79, 18-9-79, 22-10-79, 18-10-79, 29-10-79, 16-10-79, और 12-10-79 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

और

रिट याचिका संख्या 892, 918, 921, 979-980, 1057-1058, 1095, 1234, 1273, 1051, 997, 940 और 981/79

(संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

डॉ. वाई.एस. चिताले (सीए 3220/79), आर.ए. गुप्ता, आदर्श गोयल और एस. के. गोयल, सीए 3220/79 और 3222/79 में अपीलार्थी की ओर से और रिट याचिका 892,918 और 921/79 में याचिकाकर्ता की ओर से।

बी. दत्ता और के. के. मनचंदा, सीए 3221/79, 3224-3226/79 में अपीलार्थी की ओर से।

अनिल बी. दीवान, आदर्श गोयल, एस. के. गोयल और आर. ए. गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से सीए 3323/79 में।

आदर्श के. गोयल, एस. के. गोयल और आर. ए. गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से सीए 3222/79 में, डब्ल्यूपी 892/79, 918/79, 921/79 में याचिकाकर्ता की ओर से।

ए. के. गोयल और एस. के. गोयल, डब्ल्यू.पी. 979/79 में याचिकाकर्ता की ओर से।

बी. दत्ता और के. के. मनचंदा, डब्ल्यू.पी. 980/79 में याचिकाकर्ता की ओर से।

सर्व मित्तर, वेद प्रकाश गोयल और बी. एस. मलिक, याचिकाकर्ता की ओर से।

एम. पी. झा, ज्ञान चंद धुरीवाला और संजय वालिया, डब्ल्यूपी 1057-58/79 में याचिकाकर्ता के ओर से।

एम. पी. झा और पी. सी. खुंगर, डब्ल्यू.पी. 1095/79 में याचिकाकर्ता की ओर से।

एन. डी. गर्ग और टी. एल. गर्ग, डब्ल्यूपी 1234/79 में याचिकाकर्ता की ओर से।

आर. के. गर्ग (डब्ल्यूपी 892/79 और सीए 3220/79) ज्ञान सिंह और एस सी पटेल, सी ए 3220/79, 3221, 3222, 3223, 3224 में प्रतिवादी 2-3 की ओर से और डब्ल्यूपी 892/79, 921, 979, 981, 1057-58/79, 1273, 997 में प्रतिवादी की ओर से और सी ए 3230, 3225/79 में प्रतिवादी की ओर से।

हरदेव सिंह और आर. एस. सोधी, डब्ल्यूपी 918/79 और 980/79, 1095 और 1234/79 में प्रतिवादी की ओर से।

आदर्श गोयल और ज्ञान सुधा मिश्रा, डब्ल्यूपी 1273/79 में याचिकाकर्ता की ओर से।

न्यायालय का आदेश इनके द्वारा दिया गया -

कृष्णा अय्यर, न्यायाधिपति. रिट याचिकाओं का यह बड़ा समूह दिखाता है कि हमारी प्रक्रियात्मक प्रणाली में मुकदमेबाजी के प्रसार की आदत कैसे है क्योंकि मामलों पर अलग-अलग विचार किया जाता है, न कि उनके व्यापक निहितार्थों के आधार पर। और डॉकेट प्रबंधन एक कला है जो अपने भारतीय उदय की प्रतीक्षा कर रही है। जिन तथ्यों को स्वीकार किया जा रहा है, वे बहस को टाल देते हैं। इन सभी अपीलकर्ताओं और रिट याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा अधिनियम संख्या 32/1977 के तहत 3% की बढ़ी हुई दर (मूल 2 प्रतिशत से बढ़ाकर) पर बाजार शुल्क का भुगतान किया था। कई डीलरों ने वसूली को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी, और इस न्यायालय ने, अपीलों की एक शृंखला में (सी.ए.सं. 1083/1977 आदि) फैसला सुनाया कि 2% की मूल दर से 1% की अधिकता अधिकारातीत थी। इसने अवैध हिस्से को वापस करने के लिए बाजार समितियों पर परिणामी दायित्व डाला। संभवतः उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें सीधे परिमाणित नहीं किया जा सकता था। जिन याचिकाकर्ताओं ने गलती से बड़ी रकम का भुगतान कर दिया था, जो इस न्यायालय के लेवी को अवैध ठहराने के फैसले के बाद, वापसी योग्य हो गई है, वे संबंधित बाजार समितियों को इस आशय का निर्देश देने की मांग करते हैं। दायित्व या रकम के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि बाजार समितियों के पास संग्रह का लेखा-जोखा होता है और वे अतिरिक्त रकम खर्च करने को तैयार रहती हैं। वास्तव में, यदि वे सीमा अवधि के भीतर मुकदमा दायर करते हैं, तो निश्चित रूप से डिक्री का पालन किया जाना चाहिए।

परिसीमा की अवधि क्या है और क्या अनुच्छेद 226 लागू होगा, यह विवादास्पद है जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है, लेकिन हमें किसी भी बिंदु पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए नहीं कहा जाता है। जहां सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक कानूनों के तहत, लोगों के पैसे की वसूली करते हैं, जो बाद में गलत वसूली के रूप में सामने आते हैं, स्थिति का धर्म किसी भी प्रकार की बातचीत न करना स्वीकार करता है। विशेष रूप से सार्वजनिक निकायों के लिए, गलत तरीके से बरामद की गई चीज़ को उसी को लौटाने की सीमा का कोई कानून नहीं है। न ही 'वैकल्पिक उपचार' की नकारात्मक दलील पर, उच्च विशेषाधिकार रिट के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करना हमारे न्यायशास्त्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि न्याय से जुड़े कानून का मूल सिद्धांत जहाँ अधिकार है वहां उपाय है। बहुत पहले डाइसी ने लिखा था:

> "जहाँ अधिकार है वहां उपाय है, इस दृष्टिकोण से महज एक तात्विक प्रस्ताव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। संवैधानिक कानून पर इसके प्रभाव में, इसका मतलब यह है कि अंग्रेज जिनके परिश्रम से धीरे-धीरे कानूनों और संस्थानों का जटिल सेट तैयार हुआ, जिसे हम संविधान कहते हैं, उन्होंने विशेष अधिकारों को लागू करने या निश्चित गलतियों को रोकने के लिए उपाय प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मनुष्य या अंग्रेज़ों के अधिकारों की किसी भी घोषणा की तुलना में.... संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और अलग-अलग राज्यों के संविधान लिखित या मुद्रित दस्तावेजों में सन्निहित हैं, और उनमें अधिकारों की घोषणा शामिल है। लेकिन अमेरिका के राजनेताओं ने अमेरिकी संविधान द्वारा घोषित अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने के साधन उपलब्ध कराने में अद्वितीय कौशल दिखाया है।

कानून का शासन इंग्लैंड की ही तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की भी एक विशिष्ट विशेषता है।"

एक और बात। हमारे अधिकार क्षेत्र में, सामाजिक न्याय एक व्यापक उपस्थिति है; और इसलिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, न्यायिक प्रक्रिया की सेवा का दावा करने वालों से वितरणात्मक न्याय के बुनियादी नियम को अपनाने के लिए कहकर राहत की रूपरेखा तैयार करते समय, छोटे व्यक्तियों से, जिनसे वे संबंधित हैं, छोटे-छोटे लेन-देन में ली गई थोड़ी-थोड़ी रकम वापस करने की सहमति देकर समानता की रणनीति द्वारा निर्देशित होना उचित है।

जब हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को अच्छे सामरी न्यायशास्त्र के इन दिशानिर्देशों की याद दिलाई और इन मामलों के सहमति से निपटारे की इच्छा जताई, तो हमें संतुष्टिपूर्वक स्वागत योग्य प्रतिध्वनि मिली। और हम इस रुख की सराहना करते हैं।

बाजार समितियों के वकील ने बताया कि हालांकि अतिरिक्त संग्रह की वापसी कानूनी रूप से व्यापारियों के कारण हो सकती है, लेकिन कई व्यापारियों ने खुद ही अगले खरीदारों से इस अतिरिक्त प्रतिशत की वसूली कर ली है। इतना ही नहीं, यदि ये छोटे-छोटे शीर्षक मूल भुगतानकर्ताओं को लौटाने हैं, तो उन्हें अगले खरीदारों को भी वापस कर देना चाहिए। जो व्यापारी याची हैं, उन्हें इतनी छोटी रकम रखने का अधिकार बाजार समितियों से अधिक नहीं है। बेशक, जिस हद तक व्यापारियों ने अपने पास से भुगतान किया था, वे उन्हें रखने के हकदार थे, लेकिन वहां नहीं जहां उन्होंने बदले में, कहीं और से एकत्र किया था। प्रत्येक कृषक को नगण्य रकम की वसूली के लिए मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही दायर करने के लिए छोड़ना कठिन होगा, जो संचयी रूप से भारी मात्रा में होती है। बहुत से लोग एक छोटे से मिश्रण बनाते हैं। इसी तरह की स्थिति नेवाबगंज चीनी मिल [(1)] मामले में उत्पन्न हुई, जहां इस न्यायालय ने

एक नई स्थिति से निपटने के लिए एक नई प्रक्रिया तैयार की, जहां इक्विटी ने पुनर्वितरण की मांग की, लेकिन प्रक्रियात्मक महँगेपन और बोझिलता ने "छोटे" कई लोगों द्वारा इस तरह की कानूनी कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। बिना किसी मिसाल के परिस्थितियाँ बिना मिसाल के उपचार की माँग करती हैं।

हमने अधिवक्ताओं को संकेत दिया कि नेवाबगंज चीनी मिल मामले (सुप्रा) में अपनाई गई प्रक्रिया को वर्तमान मामले में उपयोगी रूप से अपनाया जा सकता है। व्यापक सिद्धांत में, अधिवक्ता सहमत हुए, और हम उस स्तर पर आगे बढ़ते हैं, कि हम बाजार समितियों द्वारा धन वापसी की एक योजना तैयार करते हैं और ऊपर बताई गई सीमा तक, उन लोगों को छोटी मात्रा में पुनर्वितरित करते हैं, जिनसे अनुचित संग्रह किया गया था। अनजाने में, उन व्यापारियों द्वारा जो अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता हैं।

अनुच्छेद 226 एक असाधारण उपाय प्रदान करता है जो अनिवार्य रूप से विवेकाधीन है, हालांकि कानूनी चोट पर आधारित है। यह अदालत के लिए पूरी तरह से खुला है, इस लचीली शक्ति का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित के निर्देशों और इक्विटी परियोजनाओं के लिए ऐसे आदेश पारित कर सकती है।

समानता के न्यायालय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए राहत देने और रोकने के लिए बहुत आगे जा सकते हैं और अक्सर ऐसा करते भी हैं, बजाय इसके कि वे वहां जाने के आदी हैं जहां केवल निजी हित शामिल होते हैं। तदनुसार, राहत देना या रोकना उचित रूप से सार्वजनिक हित के विचारों पर निर्भर हो सकता है..." [(2)]

इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित निर्देश देते हैंः

I. नीचे दिए गए निर्देशों के अधीन, विभिन्न बाजार समितियों द्वारा एकत्र की गई सभी रकम, जो इन विभिन्न रिट याचिकाओं या अपीलों में प्रतिवादी हैं रजिस्ट्रार द्वारा न्यायालय को भुगतान की जाने वाली राशि की सूचना दिए जाने के एक सप्ताह

के भीतर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

II. आज से 10 दिनों के भीतर डीलरों द्वारा अतिरिक्त एकत्रित राशि (1%) का विवरण उपरोक्त विभिन्न बाजार समितियों को प्रतियों के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि पार्टियों के बीच कोई मतभेद है इसे विविध याचिकाओं के रूप में इस न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश, यदि कोई हो, पर, इस प्रकार निर्धारित राशि को अंतिम माना जाएगा।

III. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और अन्यथा इस तथ्य को उचित प्रचार दें कि जिन डीलरों ने देनदारियों को दूसरों को नहीं दिया है और जिन लोगों ने इन रिट याचिकाओं और अपीलों में शामिल अतिरिक्त एक प्रतिशत का योगदान दिया है या भुगतान किया है। ऐसी रकम के लिए दावा कर सकता है जो उसे एक महीने या ऐसी अन्य अवधि के भीतर देय है जो वह तय कर सकता है। रजिस्ट्रार ऐसे दावों की जांच करेगा और साबित की गई रकम का पता लगाएगा। इसके बाद वह सभी संबंधित बाजार समितियों से रजिस्ट्री में ऐसी रकम के भुगतान की मांग करेगा जिसके संबंध में दावों का प्रमाण दिया गया है। ऐसी सूचना पर, बाजार समितियां ऐसी सूचना के एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान रजिस्ट्री को करेंगी। राशि का भुगतान आज से रजिस्ट्रार के पास जमा करने की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ किया जाएगा।

IV. ऊपर बताई गई तर्ज पर दावेदारों द्वारा उचित प्रमाण पर ऐसे आवधिक दावे करने के लिए रजिस्ट्रार के पास खुला होगा।

V. वह यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से दावों को संसाधित करने की प्रक्रिया तैयार करेगा और, विवाद की स्थिति में, ऐसे विवादों के निर्णय के लिए उच्च न्यायालय का

संदर्भ ले सकता है, यदि वह इसे आवश्यक समझता है। अन्यथा, वह आपत्तियों का अंतिम रूप से निस्तारण कर सकता है।

VI. यदि रिफंड के दावे की कार्यप्रणाली के संबंध में या अन्यथा इस न्यायालय से कोई और निर्देश आवश्यक पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय ऐसे मामले के बारे में इस न्यायालय को रिपोर्ट करेगा और उस पर दिए गए आदेश पार्टियों को बाध्य करेंगे।

VII. यदि राशि के पुनर्भुगतान के लिए पात्र पक्ष आज से एक वर्ष के भीतर दावा नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार किसी भी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा। ऐसी पक्षों के लिए यह खुला होगा कि वे अपनी देय किसी भी राशि की वसूली के लिए अपने उपाय अपनाएं।

VIII. प्रत्येक राज्य विपणन बोर्ड ऊपर दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रचार और अन्य प्रासंगिक खर्चों के प्रारंभिक खर्च के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष आज से 10 दिनों के भीतर 5,000/- रुपये की राशि जमा करेगा। एक वर्ष के अंत में किसी भी अप्रयुक्त राशि का भुगतान संबंधित राज्य विपणन बोर्ड को किया जाएगा।

IX. हम आगे निर्देश देते हैं कि दावा न की गई रकम, यदि कोई हो, को संबंधित विपणन समितियों द्वारा सीए संख्या 1083/77 में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई क़ानून के अंतर्गत आने वाले उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

इन अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार किया जाता है, हमारे सामने दोनों पक्ष विजेता हैं, अदृश्य छोटे उपभोक्ता और सबसे बढ़कर, अव्यक्त समुदाय के लिए न्याय, समानता और अच्छा विवेक, जो एक-दूसरे से दूरी के भीतर कार्रवाई में कानून की कार्यात्मक विजय है।

हम इस संतुष्टि के साथ समाप्त करते हैं कि प्रत्येक ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसकी मान्यता में हम पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देते हैं।

एनवीके

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****